पोषण अभियान : कुपोषण से निपटने की कारगर शुरुआत

राकेश श्रीवास्तव

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment

सही पोषण - देश रोशन

पोषण अभियान का यह पहलू पोषण संबंधी जागरूक समाज बनाने की खातिर लोगों को सक्रिय करने के लिए कई स्तर पर काम करने की तरफ इशारा करता है। जरूरतमंदों और उनके परिवारों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में सामुदायिक कार्यक्रम, मास मीडिया, मल्टीमीडिया और अन्य स्तर पर लगातार प्रचार अभियान, तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मिलकर काम करना, कुपोषण के लिए काम कर रहे स्वयंसहायता संगठन और कार्यकर्ता के जरिये इस दिशा में असरदार ढंग से काम किया जा सकता है। इसका मकसद पोषण के लिए जन आंदोलन खड़ा करना है

यह तथ्य आमतौर पर लोगों को पता है कि कुपोषण की कोई एक वजह नहीं होती, बल्कि यह कई तरह की गड़बड़ियों और असंतुलन का नतीजा होता है। ये गड़बड़ियां कुपोषण के लगातर बने रहने में मददगार होती हैं। इसके कारण हम पीढ़ी दर पीढ़ी जरूरी मानव संसाधन जुटाने में अक्षम हो जाते हैं। संसाधनों संभावनाओं के भरपूर इस्तेमाल और भारत को वैश्विक महाशक्ति की भूमिका निभाने के लिए हमें कुपोषण को जड़ से खत्म करने पर फोकस करना होगा, ताकि आगामी पीढ़ियों को सेहतमंद बनाने का काम सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बेहतर बौद्धिक संभावनाओं के लिए भी गुंजाइश बनाई जा सके, जिससे काम संबंधी उत्पादकता में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

यह एक चीज हमें *मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया* जैसे विभिन्न अभियानों से जुड़े खालीपन को भरने में मददगार होगी और एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ने की हमारी संभावनाओं का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा।

प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान की शुरुआत की। यह बेहतर पोषण के लिए प्रधानमंत्री की बेहद अहम योजना है। इस अभियान का मकसद तकनीक केंद्रित रवैये और समेकन के जरिये कुपोषण, रक्तहीनता और बच्चों में कम वजन की समस्या को दूर करने के लिए काम करना है। साथ ही, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर फोकस करने की बात है यानी कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम का मकसद सेवाएं सुनिश्चित करना और तकनीक, व्यवहार संबंधी बदलाव के जरिये इस संबंध में तय लक्ष्य हासिल करना है। इसके तहत अगले कुछ साल में अलग-अलग मापदंडों पर कुछ खास लक्ष्य भी तय किए गए हैं।

इस अभियान के लिए चौतरफा प्रयास के तहत सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से इसके दायरे में लाया जाएगा। 2017-18 में 315 जिलों में इस पर काम करने की बात है, जबकि 2018-19 में अन्य 235 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद बाकी जिलों में 2019-20 के दौरान इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा। देश में पहले कभी उच्चस्तर पर कुपोषण की समस्या से निपटने को इतनी अहमियत नहीं दी गई थी।

कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए फिलहाल केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग मंत्रालय/विभाग अपने-अपने स्तर पर काम करते हैं। इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सबसे उच्च स्तर की एजेंसी हैं। लिहाजा, कुपोषण की चुनौती से असरदार ढंग से निपटने की खातिर तमाम संबंधित इकाइयों के बीच समन्वय बनाने की जरूरत है। पोषण अभियान इस तरह की सभी स्कीमों की खातिर समन्वय संबंधी जरूरी प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। इससे कुपोषण की दिशा में

लेखक महिला और बाल विकास विकास मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। उनके पास पोषण, महिला कल्याण और बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने का काफी अनुभव है। ईमेल: secy.wcd@nic.in

आरेख 1 : पोषण अभियान के पहलू

समन्वित तरीके से काम करने को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के लिए कुपोषण राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारी समिति का गठन किया है और इसके जरिये केंद्र सरकार इस दिशा में संमिलन का लक्ष्य हासिल करेगी। दोनों कमेटियों में पोषण अभियान से जुड़े सभी संबंधित पक्षों के सदस्य शामिल होंगे। इसी तरह, राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर संमिलन कार्य योजना (कन्वर्जेंस एक्शन प्लान) इस अभियान के अमल और निगरानी के लिए तंत्र बनाने में मददगार साबित होगा। वीएचएसएन दिवस सभी प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी के लिए गांव स्तर पर समन्वय का मंच मुहैया कराता है।

यह अभियान प्रमुख कार्यकर्ताओं मसलन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला सुपरवाइजर को स्मार्टफोन मुहैया कराकर उन्हें साधनों से लैस करेगा। इस मकसद के लिए खासतौर पर आईसीडीएस-कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर नामक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन तैयार किया है, जो डेटा हासिल करने, सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर सक्रिय भूमिका निभाने के बारे में जागरूक करता है। इसके बाद इस डेटा को निगरानी के लिए रियल टाइम आधार पर डैशबोर्ड के जरिये ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निरीक्षण करने वाले स्टाफ को मुहैया कराया जाता है। मोबाइल खरीदकर उसे बांटना इस परियोजना का हिस्सा है। इस एप्लिकेशन का मकसद आईसीडीएस सर्विस डिलीवरी में सिस्टम को और मजबूत करना और असरदार तरीके से निगरानी और सही समय पर दखल के जरिये पोषण संबंधी बेहतर नतीजे पेश करना है। यह सॉफ्टवेयर डेटा को जमीनी स्तर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (मोबाइल और टैबलेट) में लेने में मदद करता है। इसके जरिये आईसीडीएस सर्विस डिलीवरी से जुड़ी सूचनाओं को इकट्ठा करना और नियमित आधार पर पोषण अभियान के नतीजों के बारे में जानना मुमकिन होता है। यह सूचना वेब आधारित डैशबोर्ड पर रियल टाइम आधार पर राज्यों और एमडब्ल्यूसीडी के लिए उपलब्ध है। इसका मकसद आईसीडीएस सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना, मिशन के लिए प्रभावकारी ढंग से योजना तैयार करना व तथ्य आधारित फैसले लेना है। कुपोषण की समस्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती है और यह कई चीजों पर निर्भर है। मसलन नवजात और छोटे बच्चों के स्तनपान का प्रचलन, बचाव, संस्थागत डिलीवरी, बचपन की शुरुआती अवस्था में विकास, खान-पान की मजबूती, कृमि से मुक्ति, पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता व उचित साफ-सफाई, खान-पान की विविधता और अन्य संबंधी चीजें। लिहाजा, कद नहीं बढ़ने, कम वजन (खासतौर पर बच्चों में) आदि की समस्या से निपटने के लिए सतत प्रयास की जरूरत है। इसके तहत कई स्तरों पर काम करना होगा और जमीनी स्तर पर तालमेल और समन्वय की जरूरत होगी। बहरहाल, इस समस्या से सामाजिक-व्यवहार संबंधी बदलाव से ही निपटा जा सकता है।

पोषण अभियान का यह पहलू पोषण संबंधी जागरूक समाज बनाने की खातिर लोगों को सक्रिय करने के लिए कई स्तर

आरेख 2 : आमेलन (कन्वर्जेन्स) प्रवाह चक्र

महिला और बाल विकास मंत्रालय	• आंगनवाड़ी सेवाएं • प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना • किशोरियों के लिए योजना	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• जनानी सुरक्षा योजना • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
पेयजल और सफाई मंत्रालय	• स्वच्छ भारत मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) • आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	• सार्वजनिक वितरण प्रणाली	पंचायत राज मंत्रालय	• संमिलन की दिशा में ग्राम पंचायतों को इकट्ठा और सक्रिय करना
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	जनजातीय मामलों का मंत्रालय	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, एचआरडी मंत्रालय	शहरी विकास मंत्रालय

आरेख 3 : आईसीडीएस: कॉमन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर

पर काम करने की तरफ इशारा करता है। जरूरतमंदों और उनके परिवारों में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में सामुदायिक कार्यक्रम, मास मीडिया, मल्टीमीडिया और अन्य स्तर पर लगातार प्रचार अभियान, तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मिलकर काम करना, कुपोषण के लिए काम कर रहे स्वयंसहायता संगठन और कार्यकर्ता के जरिये इस दिशा में असरदार ढंग से काम किया जा सकता है। इसका मकसद पोषण के लिए जन आंदोलन खड़ा करना है।

इस अभियान को पूरी तरह से लागू करने की खातिर महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस अभियान का इरादा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए तमाम संबंधित मंत्रालयों द्वारा मिलकर काम करना है। इससे पहले भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी इतने सारे कार्यक्रम एक साथ नहीं चलाए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय हर 6 महीने पर इसकी प्रगति की समीक्षा करेगा और राज्य स्तर पर भी ऐसी ही समीक्षा का अनुमान है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तिमाही आधार पर जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की 10 तारीख को हर जिले में डीएम की तरफ से अंजाम दिया जाएगा। जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) में बताया गया है, अंतरराज्यीय और अंतरजिला स्तर पर कुपोषण के मामले में भिन्नता काफी ज्यादा है। लिहाजा, हर राज्य/जिले को अपनी संमिलन कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है, जिसमें उनकी दिक्कतों और बाधाओं का जिक्र होगा। साथ ही, यह भी बताया जाएगा कि छोटी, मध्य या लंबी अवधि में इससे कैसे निपटा जा सकता है।

देश भर में कुपोषण की समस्या में चमत्कारी बदलाव की उम्मीद करने से इस दिशा में तमाम जरूरी प्रक्रियाओं पर काम करना बेहद जरूरी है। इस अभियान के तहत सेवाओं की बेहतर डिलीवरी पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के लिए एक साथ लक्ष्य हासिल करने पर टीम आधारित इनाम और इस लक्ष्य को जल्द हासिल करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस सिलसिले में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/जिलों/प्रखंडों/आंगनवाड़ी केंद्रों की मदद भी की जाएगी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

बहरहाल, पोषण अभियान का मकसद तमाम संबंधित पक्षों को एकजुट कर सब को जवाबहेदी और जिम्मेदारी सौंपना है, ताकि भारत को अपने 130 करोड़ के मानव संसाधन की संभावनाओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद मिल सके। ❑